

बोर्ड ने तैयार किया आधुनिक पाठ्यक्रम

सत्र आरंभ होने से पहले सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पहुंचेंगी : डा. राजेश

जगरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के

विद्यार्थियों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनर्गठित और आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ने

को मिलेगा। बोर्ड ने नई पुस्तकों की छपाई और समयबद्ध आपूर्ति के

लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बोर्ड की तैयारियों पर जानकारी साझा की है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में वैचारिक समझ और नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए किया है। इन पुस्तकों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे विद्यार्थियों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। बोर्ड का लक्ष्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है।

उन्होंने कहा कि शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की अधिकांश कक्षाओं के लिए पुस्तकों



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, पुस्तकें ऐसे तैयार की हैं कि विद्यार्थियों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले

की छपाई लगभग पूरी हो चुकी है। शेष कार्य भी अंतिम चरण में है। बोर्ड सुनिश्चित कर रहा है कि सरकार की ओर से निर्धारित समयसारणी के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पुस्तकें समय पर पहुंचाई जाएं ताकि शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई आरंभ हो सके। इस बार पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डा. शर्मा के अनुसार, पुस्तकों के निर्माण में विषय विशेषज्ञों, अनुभवी शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सुझावों को शामिल किया गया है। इससे न केवल विषय-वस्तु अपडेट हुई है, बल्कि भाषा को भी इतना सरल रखा गया है कि विद्यार्थी इसे आसानी से समझ सकें।

विद्यार्थियों की करियर काउंसिलिंग करेंगे शिक्षक

राज्य ब्यूरो, जगरण • शिमला : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में करियर जागरूकता की कमी को लेकर शिक्षा विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। विभाग ने सभी उपनिदेशकों (स्कूल एवं उच्च शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में करियर काउंसिलिंग और मार्गदर्शन व्यवस्था को प्रभावी रूप से मजबूत किया जाए। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों के छात्र नीट जेईई, सीयूईटी, सीएलएटी और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते।

उन्होंने कहा कि जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में कई योग्य छात्र समय पर आवेदन नहीं कर

उपनिदेशकों को निर्देश, मार्गदर्शन व्यवस्था को किया जाए मजबूत जानकारी के अभाव में योग्य छात्र समय पर आवेदन नहीं कर पाते

पाते, जिससे वे महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों से आते हैं। ऐसे में करियर काउंसिलिंग और सही मार्गदर्शन की कमी उनकी प्रगति में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी जाए। नियमित करियर मार्गदर्शन और काउंसिलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। विभिन्न करियर विकल्पों, पात्रता, समय-सीमा और आवेदन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया जाए।

प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी तरह ऑनलाइन होगी : शिक्षा बोर्ड सचिव

धर्मशाला, 30 जनवरी (प्रियंका) : प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे छात्रों, संस्थानों और विभागों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने एक विशेष बातचीत पर यह बात कही। डा. शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में विभिन्न संस्थान और विभाग प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए बोर्ड से संपर्क करते हैं। इसे सरल और तेज बनाने के लिए ऑनलाइन वैरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता की पुष्टि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हो सकेगी।

इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी। बोर्ड सचिव ने बताया कि डुप्लीकेट प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था को भी डिजिटल किया जा रहा है। आने वाले समय में डुप्लीकेट सर्टीफिकेट को आधार से लिंक कर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगे और छात्रों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

पंजाब
केसरी
विशेष
बातचीत

नई शिक्षा नीति के तहत बदला प्रश्नपत्रों का स्वरूप

डा. शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रश्नपत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब परीक्षाओं में रटने की बजाय समझ, विश्लेषण और कॉन्सैट आधारित प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, जिससे छात्रों की वास्तविक योग्यता सामने आ सके।



अभिभावकों और शिक्षकों के लिए संदेश

शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों का मूल्यांकन केवल अंकों के आधार पर न करें, बल्कि उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता और नैसर्गिक गुणों को समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है और उसकी प्रतिभा भी अलग दिशा में विकसित हो सकती है। वहीं शिक्षकों से डा. शर्मा ने आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को केवल

सैद्धांतिक पढ़ाई तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल, तकनीक और ए.आई. आधारित शिक्षण पद्धतियों से जोड़ें। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए भी बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने कहा कि परीक्षा में विद्यार्थियों की असफलता का कारण केवल पाठ्यक्रम नहीं होता, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता एक निर्णायक भूमिका निभाती है।

सेना से शिक्षा प्रशासन तक का सफर

डा. मेजर विशाल शर्मा का जन्म 18 अगस्त 1978 को ज्वाली, जिला कांगड़ा में हुआ। उन्होंने 8 फरवरी 2003 को भारतीय सेना में सेवा शुरू की और लगभग साढ़े 8 वर्षों तक देश की सेवा की। इसके बाद नवम्बर 2011 में उन्होंने हिमाचल प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की। वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल को रोकने के लिए बहुस्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्लाईग स्वर्कॉड, उपमंडल

दंडाधिकारी (एस.डी.एम.), डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर स्तर के अधिकारी तथा सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

बोर्ड ने तैयार कीं आधुनिक पाठ्य-पुस्तकें सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में पहुंचेंगी किताबें

धर्मशाला, 30 जनवरी (ब्यूरो) : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बोर्ड की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पूरी तरह से पुनर्गठित और आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। बोर्ड ने नई पुस्तकों की छपाई और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई है। डा. राजेश का कहना है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की अधिकांश कक्षाओं के लिए पुस्तकों की छपाई लगभग पूरी हो चुकी है। शेष कार्य भी अब अपने अंतिम चरण में है।

बोर्ड यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी सरकारी और संबद्ध निजी विद्यालयों तक पुस्तकें समय पर पहुंचा दी जाएं, ताकि शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। डा. राजेश का कहना है कि इस बार पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुस्तकों के निर्माण में विषय-विशेषज्ञों, अनुभवी शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है। इससे न केवल विषयवस्तु अपडेट हुई है, बल्कि भाषा को भी इतना सरल रखा गया है कि छात्र स्वयं भी उसे आसानी से समझ सकें।

स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए बोर्ड द्वारा कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम में चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया गया है, ताकि शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, कौशल-आधारित और आधुनिक बनाया जा सके। डा. शर्मा ने बताया कि सबसे पहले वर्ष 2022-23 में कक्षा 1, 2 पाठ्य-पुस्तकों में बदलाव किया गया। इन कक्षाओं में रटने की बजाय बुनियादी समझ,

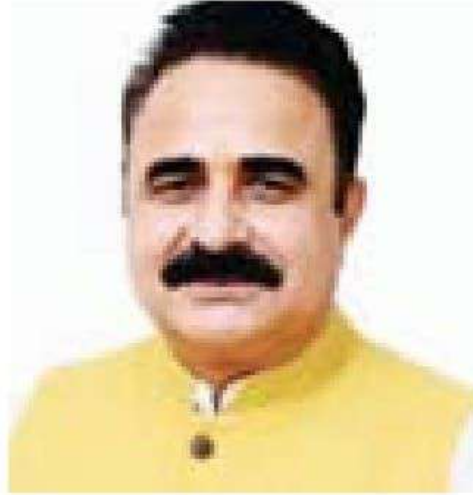
गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने की रुचि को प्राथमिकता दी गई है। डा. विशाल ने कहा कि आने वाले समय में पाठ्यक्रम की निरंतर समीक्षा की जाएगी। डा. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रों की अंकतालिकाएं पहले से ही डी.जी. लॉकर पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे उच्च शिक्षा, रोजगार और अन्य प्रक्रियाओं में दस्तावेज प्रस्तुत करना आसान हुआ है।

हिमाचल बोर्ड ने तैयार की आधुनिक पाठ्य-पुस्तकें, सत्र शुरू होने से पहले सरकारी व निजी स्कूलों में पहुंचेंगी

धर्मशाला (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बोर्ड की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि

ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की अधिकांश कक्षाओं के लिए पुस्तकों की छपाई लगभग पूरी हो चुकी है : डॉ. राजेश शर्मा

प्रदेश के विद्यार्थियों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (हृदयक) के अनुरूप पूरी तरह से पुनर्गठित और आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। बोर्ड ने नई पुस्तकों की छपाई और समयबद्ध आपूर्ति के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि नई पाठ्य-पुस्तकों



का निर्माण केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में वैचारिक समझ और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए किया गया है। इन पुस्तकों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे बच्चों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। बोर्ड का लक्ष्य छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है। पुस्तकों की उपलब्धता पर अपडेट देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र वाले

स्कूलों की अधिकांश कक्षाओं के लिए पुस्तकों की छपाई लगभग पूरी हो चुकी है। शेष कार्य भी अब अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी सरकारी और संबद्ध निजी विद्यालयों तक पुस्तकें समय पर पहुँचा दी जाएं, ताकि शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। इस बार पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डॉ. शर्मा के अनुसार, पुस्तकों के निर्माण में विषय-विशेषज्ञों, अनुभवी शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है। इससे न केवल विषय-वस्तु अपडेट हुई है, बल्कि भाषा को भी इतना सरल रखा गया है कि छात्र स्वयं भी उसे आसानी से समझ सकें।

शिक्षा बोर्ड ने तैयार की आधुनिक पाठ्य-पुस्तकें

अनंत ज्ञान

◆ सत्र शुरू होने से पहले सरकारी व निजी स्कूलों में पहुंचेंगी किताबें

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बोर्ड की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पूरी तरह से पुनर्गठित और आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। बोर्ड ने नई पुस्तकों की छपाई और समयबद्ध आपूर्ति के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।



सरकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी सरकारी और संबद्ध निजी विद्यालयों तक पुस्तकें समय पर पहुंचा दी जाएं, ताकि शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके।

विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार हुआ कंटेंट: इस बार पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डॉ. शर्मा के अनुसार, पुस्तकों के निर्माण में विषय-विशेषज्ञों, अनुभवी शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है। इससे न केवल विषय-वस्तु अपडेट हुई है, बल्कि भाषा को भी इतना सरल रखा गया है कि छात्र स्वयं भी उसे आसानी से समझ सकें।

अंतिम चरण में छपाई, समय पर मिलेगी डिलीवरी: पुस्तकों की उपलब्धता पर अपडेट देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र वाले स्कूलों की अधिकांश कक्षाओं के लिए पुस्तकों की छपाई लगभग पूरी हो चुकी है। शेष कार्य भी अब अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड यह सुनिश्चित कर रहा है कि

रट्टा पद्धति का अंत, व्यावहारिक ज्ञान की शुरुआत

डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि नई पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में वैचारिक समझ और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए किया गया है। इन पुस्तकों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे बच्चों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। बोर्ड का लक्ष्य छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है।